आधुनिक युग के बर्बर?

सुभाष गाताडे

NEW DELHI : The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) is furious with an American thinktank for declaring it a terrorist organisation and lumping it with a host of jihadi organisations and secessionist outfits.

The Sangh leadership has written to the Terrorism Research Centre, protesting against the 'terrorist' tag, but is yet to get a response...

The 38 shortlisted to give the Sangh company include jihadi biggies like Lashkar-e-Toiba and Hizbul Mujahideen which have been declared Foreign Terrorist Organisations by the US. The RSS's hardcore ideological foe, the jamaat-Islami, too has found a place.

(US think-tank calls RSS terrorist, Sangh fumes, MOHUA CHATTERJEE, TIMES NEWS NETWORK [FRIDAY, MAY 27, 2005, 08:18:15 AM])

कहा जाता है कि मुसीबतें अकेले नहीं आतीं, इकट्ठे आती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक स्वघोषित 'सांस्कृतिक संगठन' पर तो गोया मुसीबतों की बारिश हो रही है। कहां तो

अरमान धरे थे अपने आनुषंगिक संगठन भाजपा के ज़रिए 'इंडिया शाईनिंग' की दूसरी क़िस्त शुरू करने के, कहां तो वादा था समूचे मुल्क के सामने गुजरात के 'सफल प्रयोग' का एक और सुधरा हुआ संस्करण पेश करने का और अब यह आलम है कि अपने अनुशासन के लिए जानी गई इस जमात में, 'एकचालकानुवर्तित्व' पर टिके इस संगठन में लोग संघ सुप्रीमो की राय तक को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और फ़िलवक़्त 'हिंदू राष्ट्र' बनना तो दूर रहा राममंदिर, समान नागरिक संहिता जैसा त्रिसूत्री एजेंडा साकार होता नहीं दिख रहा।

ग़नीमत यही है कि जिन-जिन सूबों में संघ के मुरीद हुकूमत संभाल रहे हैं वे बड़ी निष्ठा के साथ हेडगेवार-गोलवलकर के पथ का अनुगमन कर रहे हैं। कहीं मनुमहाराज के एजेंडे को पूरा करने की कसम खाए हुए सती के महिमामंडन में लगे हैं, कहीं गायों के व्यापार में लगे दलितों पर हमले कर रहे हैं तो कहीं कुछ न कुछ बहाना बनाकर धरती के अपने हिस्से को 'यवनों' से मुक्त कर रहे हैं, तो कहीं ईसाईपुत्र ग्राहम स्टैन्स के हत्यारे दारा सिंह के नाम से दारा सेना बनाकर क़वायद कर रहे हैं।

अलबत्ता यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली के तख़्त से भाजपा को मिली शिकस्त का मामला समूचे संघ कबीले पर भारी पड़ता दिख रहा है। न केवल मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी अपनी पुरानी 'अनटचेबल' की हालत बनने के आसार दिख रहे हैं। चंद्राबाबू नायडू अपनी 'साइकिल' पर पहले ही विदा हो चुके थे, अब शिवसेना के अंदर भी रिश्तों को तोड़ने की सुगबुगाहट दिख रही है। उधर संघ कबीले को अपने जिस 'पोस्टर बॉय' नरेंद्र मोदी पर सबसे ज़्यादा नाज़ था उसे अपने मुल्क में आने से वीसा देने से इंकार करके अमेरिका ने जहां उसे घता बताया है वहीं अब अमेरिकी हुकूमत से क़रीबी 'आतंकवाद' के अध्ययन पर केंद्रित एक सेंटर ने भारत में 'सक्रिय अड़तीस आतंकवादी संगठनों' की लश्कर-ए-तोइबा, जैश-ए-मोहम्मद, जमाते इस्लामी, उल्फा जैसे संगठनों से सजी फेहरिस्त में 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' का नाम शुमार करके समूचे संघ कबीले के वजूद पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है।

यह अकारण नहीं कि मई के आख़िरी सप्ताह में जब से राष्ट्रीय अख़बारों में यह ख़बर छपी है तबसे ईस्ट वर्जिनिया स्थित 'टेररिज़्म रिसर्च सेंटर' द्वारा संचालित वेबसाईट www.terrorism.com पर जाकर वहां सर्फिंग करनेवालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। भारत में बसे लोग ही नहीं अलग-अलग मुल्कों में फैले आप्रवासी भारतीय भी जानना चाह रहे हैं कि आख़िर माज़रा क्या है? पिछले लगभग अस्सी सालों से बनाई गई 'सांस्कृतिक छवि' पर आख़िर क्यों अचानक आंच आ गई है। दिक़्क़त दरअसल इस बात से भी बढ़ गई है कि जिस 'टेररिज़्म रिसर्च सेंटर' ने इस आकलन को पेश किया है वह अपने कामों के लिए अमेरिकी सरकार से भी सहायता हासिल करता है और इसके कई निदेशक और अनुसंधानकर्ता अमेरिकी प्रशासन के साथ नजदीकी से जुड़े रहे हैं।

वैसे संघ की ओर से सेंटर के नुमाइंदों को पत्र लिखा गया है कि वे 'आतंकवादी संगठनों' की सूची में 'राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ' के नाम हटा दें, लेकिन अख़बार के मुताबिक़ इस 'सांस्कृतिक संगठन' की इस गुजारिश को सेंटर ने अनसुना कर दिया है। एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि आख़िर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेंटर द्वारा पेश किए गए इस आकलन के बारे में प्रतिक्रिया ज़ाहिर करने में इतने महीने का समय क्यों जाया किया? जानने योग्य है कि सितंबर 2004 में ही इस वेबसाइट पर यह आकलन पहली दफ़ा पेश किया गया था। हिंदोस्तां से निकलने वाली एक पत्रिका *Milli Gazette*, (16-30 सितं 2004) में तो यह समाचार 16 सितंबर, 2004 के अंक में ही दिया गया था। आख़िर इतने लंबे मौन की क्या वजह रही? मुमकिन हो अपने आनुषंगिक संगठन भाजपा के सत्ता से बेदखल होने के बाद समूचा संघ परिवार सदमे की हालत में आ गया हो कि उसमें समाचारों

का जवाब देने का साहस भी न बचा हो? यह भी मुमकिन है कि उन दिनों समूचे संघ कबीले में ज़बरदस्त आपसी संघर्ष शुरू हो गया हो कि इन छोटी-मोटी बातों से उसे फुरसत न रही हो। जो भी कारण रहा हो, लेकिन सवाल कुलबुलाता रह ही जाता है।

लुब्बेलुआब यही कि बीत गए वे दिन जब अटल-आडवाणी की जोड़ी अपने आपको इस 'सभ्यतात्मक संघर्ष' में दुनिया की इस महाशक्ति अमेरिका का पार्टनर घोषित कर रही थी, और जब हिंदुत्व ब्रिगेड के विचारक अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक एवम् स्वाभाविक गठजोड़ को लेकर इतराया करते थे! शायद अमेरिकी आक़ाओं से लंबी वफ़ादारी का यही सिला हिंदुत्व के कारिंदों के लिए बदा था?

"वे जुनूनी जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वे आतंकवादियों से भी बदतर हैं और किसी बाहरी दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं।"

बेस्ट बेकरी मामले में आला अदालत द्वारा दिए गए फ़ैसले से

'टेररिज़्म रिसर्च सेंटर' द्वारा संघ परिवार के बारे में पेश किए गए आकलन को लेकर कुछ कहने के बजाय (जो निश्चित तौर पर ज़्यादा समय एवं स्थान की मांग करता है), पुराने रेकॉर्ड को टटोल कर यह जानने की कोशिश की जाए कि क्या यह पहला मौक़ा है कि हिंदुत्व ब्रिगेड या उसकी आनुषंगिक जमातों या उनकी गतिविधियों को 'आतंकवाद' की श्रेणी में शामिल किया गया है?

अभी दो साल पहले की ही बात है जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चंद संगठनों की वेबसाइटों को 'विदेशी आतंकवादी संगठनों' की सूची में डाला था जिनमें चार जियनवादी वेबसाइटें भी शामिल थीं। (by Jerry Seper, The Washington Times)' रिपोर्ट में बताया गया था :

दो अतिवादी यहूदी समूहों द्वारा संचालित चार वेबसाइटों को स्टेट डिपार्टमेंट की 'विदेशी आतंकवादी संगठनों' की सूची में डाल दिया गया है। यह पहला मौक़ा है जब इसमें इंटरनेट साईटों को भी शामिल किया गया है। 9 अक्तूबर को विभाग द्वारा घोषित की गई विश्व के आतंकवादी संगठनों की सालाना सूची में कच (Kach) तथा उसकी सहयोगी कहाने चाय (Kahane Chai) द्वारा संचालित चार वेबसाइटें शामिल की गई हैं जिन्हें विभाग ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

दिलचस्प बात है कि इनमें से वेबसाइट www.kahane.org के 'विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के आदर्शों को बढ़ाने तथा समर्थन में लगी' www. hinduunity.org के साथ नजदीकी संबंध रहे हैं। उन दिनों Hinduunity.org नाम से यह वेबसाइट के www.kahane.org के साथ अपने हाईपरलिंक को प्रदर्शित भी करती थीं। अमेरिका में बसे सेक्युलर कार्यकर्ताओं को यह बात पहले से ही पता थी कि हिंदूयूनिटी डाट आर्ग की वेबसाइट को एक साझे सर्वर पर कहाने डाट आर्ग ने ही जगह दी है तथा उनका आई पी पता (IP address) एक ही है। उनका विवरण इस प्रकार था : devserver. gwsystems. co.il (67.153.104.163) (Ref. Notice recently published in the Federal Register. (Federal Register: October 10, 2003 (Vol. 68, Number 197) Page:58738A58739) निश्चित ही रैडिकल जियनवादी समूहों के हिंदुत्व समूहों के रिश्ते किसी से छिपे नहीं रहे हैं, दोनों के सामने मुसलमान के रूप में अपना साझा दुश्मन मौजूद है।

लगभग ढाई साल पहले अमेरिका में बसे सेक्युलर तथा वामपंथी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके "द फॉरेन एक्स्चेंज ऑफ हेट' : आई डी आर एफ एंड द अमेरिकन फंडिंग ऑफ हिंदुत्व' नाम से एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया था (नव 2002)। प्रस्तुत रिपोर्ट में अमेरिका में बसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित 'इंडिया डेवलपमेंट रिलीफ फंड' (आई डी आर एफ) नामक पंजीकृत संगठन द्वारा

अमेरिका में सालाना चैरिटी/धर्मादाय के नाम पर इकट्ठा किए जाते रहे फंड और यहां उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को दहशत में रखने तथा अन्य 'पारिवारिक' कामों के लिए करने के मसले पर रोशनी डाली गई थी। इस अध्ययन में इस बात का विस्तृत विवरण दिया गया था कि किस तरह संघ परिवार के आप्रवासी सदस्यों ने इस फंड का गठन किया तथा किस तरह उससे एकत्रित पैसे का 83 फीसदी से ज़्यादा इस्तेमाल संघ परिवार के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के काम में किया जा रहा है। इसके लिए शुरू की गई 'मुहिम' का अनुमान यह भी है कि संघ परिवार की सालाना आय का लगभग 15 से 20 फीसदी इसी तरह कार्पोरेट क्षेत्र के दान-दक्षिणा से बटोरा जाता है।

प्रस्तुत रपट के जारी होने का इतना असर दिखा कि रपट के तत्काल बाद आई डी आर एफ को सालाना सहयोग देनेवाली विभिन्न बहुदेशीय कंपनियों ने तय किया कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगी। सिस्को तथा अन्य कई नामीगिरामी कंपनियों ने जहां आई डी आर एफ को दी जानेवाली धर्मादाय राशि को तत्काल खत्म करने का फैसला लिया, वहीं माईक्रोप्रोसेसर तैयार करनेवाली बड़ी कंपनी इंटेल ने भी यह सूचना भेजी है कि वह आई डी आर एफ के कामकाजों की समीक्षा करके ही आगे का फैसला लेंगे तथा तब तक यह सहयोग निलंबित रहेगा।

लंदन से प्रकाशित *फाईनान्शियल टाईम्स* ने इस सिलसिले में 'सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने वाले तत्त्वों को धन की आपूर्ति बंद करो' ('Cut the flow of funds to instigators of secatrian violence' (INDIA'S HARD MEN, page 16, 24 Feb. 2003) लेख प्रकाशित किया था। गुजरात जनसंहार में मारे गए 2000 के करीब निरपराध लोगों (जिनका बहुलांश अल्पसंख्यक थे) तथा जिसमें संलिप्त होने के लिए देश-दुनिया के मानवाधिकार संगठनों द्वारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराए जाने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत लेख में लिखा गया था : 'फाईनान्शियल टाइम्स द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि इन समूहों को विदेशों में बसे भारतीयों से काफी पैसा मिलता है जो अमेरिका तथा ब्रिटेन में करमुक्त चैरिटी डोनेशन के रूप में इकट्ठा किया जाता है...विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पीछे एक अर्द्धसैनिक निकाय के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखता है जो हिंदू पुनरुत्थानवादी भाजपा का भी मातृसंगठन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 'फासीवाद के भारतीय संस्करण' के रूप में वर्णित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे मोर्चा संगठनों के एक नेटवर्क के केंद्र में विराजमान है। यह संरचना उसे पैसा इकट्ठा करने में दूरी बनाए रखने और सहूलियत प्रदान करती है। इससे उसे यह भी सुविधा होती है कि मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के मामले से वह अपने आपको दूर रखे।'

इस बात का उल्लेख किया जाना ज़रूरी है कि अमेरिका स्थित उपरोक्त चैरिटी संगठन 'इंडिया डेवलपमेंट रिलीफ फंड' ने इन आरोपों का जवाब देते हुए भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस बात से इंकार किया था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता नहीं रखता है और भारत में सांप्रदायिक नफ़रत बढ़ाने में उसका योगदान नहीं है (Not funding hate, says IDRF, Hindu June 15, 2003) लेकिन किसी ने भी इस प्रत्युत्तर को गंभीरता से नहीं लिया।

आधुनिक समय के 'नीरो' इधर-उधर देख रहे थे जब बेस्ट बेकरी में मासूम बच्चे और महिलाएं जल रही थीं और शायद इसी बात पर विचार कर रहे थे कि अपराध को अंजाम देनेवालों को किस तरह बचाया या सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे 'बेलगाम लोगों' के हाथों में कानून और न्याय खिलौना बन जाते हैं।

(बेस्ट बेकरी मामले में आला अदालत द्वारा दिए गए फैसले से)

फिलवक़्त यह कहना मुश्किल है कि अगर 'टेररिज्म रिसर्च सेंटर' अपने दावे पर अडिग रहता है तो संघ परिवारी लोग क्या करेंगे? उनके सामने कई रास्ते खुले हैं। अलबत्ता साईबर कानूनों के लचीलेपन को देखते हुए और 'आतंकवाद की अवधारणा में अंतर्निहित व्यापकता' को देखते हुए यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसे इस मसले पर कामयाबी मिलेगी ही। शायद इसी एहसास की वजह से पिछले दिनों संघ प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि दुनिया में 54 लाख से ज़्यादा वेबसाइटें हैं और किसी ख़ास वेबसाइट पर क्या लिखा गया है उससे उन पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। ज़ाहिर है यह खिसियानी बिल्ली के खंभा नोंचने जैसी हरकत है।

निश्चित तौर पर 'आतंकवादी संगठनों की' फेहरिस्त में अपने आपको पाकर संघ परिवार में ऊपर से नीचे तक फैली बेचैनी एक ऐसा वक़्त भी है कि अस्सी साल पुराना यह 'सांस्कृतिक संगठन' इस बात का कोई जवाब ढूंढ़े कि उसकी छवि ऐसी क्यों बनी है? क्या यह महज 'सेक्युलर तालिबानी' (बकौल जनाब तरुण विजय) प्रचार का मामला है जिसने उसके ख़िलाफ़ इस स्थिति को बनाया है या उसके अपने विश्वदृष्टिकोण में ही कुछ खोट है या उससे संबंधित संगठनों की गतिविधियों की दिक़्क़तों का ही मामला है कि लोग उस पर तरह-तरह का दोषारोपण करते रहते हैं।

क्या हेडगेवार द्वारा स्थापित एवं गोलवलकर द्वारा पल्लवित-पुष्पित यह संगठन इस बात का आत्मपरीक्षण करने के लिए कभी तैयार होगा कि यह महज 'नवसाम्राज्यवादी' पूर्वाग्रह का ही मामला है कि 'टेररिजम रिसर्च सेंटर' के लोगों ने उसकी प्रकृति पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं या सभ्य समाज के मानस के प्रतिकूल दिखनेवाली गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का मामला है कि उसके विरोधियों के हाथ में नए औज़ार प्रदान किए हैं?